एन.आई. सी. उत्तर प्रदेश द्वारा जिला सूचना-विज्ञान अधिकारियों (डी.आई.ओ.) हेतु आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।

राज्य में डिजिटल सुशासन, ऑनलाइन सुरक्षा सुदृढ़ीकरण तथा अभिनव सूचना प्रौद्योगिकी नवाचारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश केंद्र द्वारा सभी जिला सूचना-विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारियों (DIOs/ADIOs/DIAs) की राज्य स्तरीय संगोष्ठी एवं तकनीकी संवाद का आयोजन 26-27 फरवरी 2026 को योजना भवन, लखनऊ में किया गया। इस कार्यक्रम में NIC उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता की।

इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर संचालित डिजिटल सेवाओं की प्रगति एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी नवाचारों से अवगत कराना तथा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक समन्वित एवं दूरदर्शी कार्यनीति विकसित करना था।

उद्घाटन एवं अभिभाषण सत्र:

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री आशेष कुमार अग्रवाल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी (SIO), के स्वागत संबोधन से हुआ। अपने उद्बोधन में उन्होंने जिला स्तर पर डिजिटल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, बेहतर समन्वय तथा नवाचार आधारित कार्यप्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि डॉ. राजेश कुमार मिश्रा, राज्य समन्वयक, एन.आई. सी. उत्तर प्रदेश, एवं विशिष्ट वक्ता डॉ शर्मिष्ठा दासगुप्ता, हेड ऑफ ग्रुप (AI Division) को पौधा भेंट कर औपचारिक रूप से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

कार्यक्रम के प्रथम सत्र में इंडस्ट्री पार्टनर डॉ नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विविध आयामों पर सारगर्भित प्रस्तुति दी गई। उन्होंने एआई में गुणवत्तापूर्ण डेटा की भूमिका, डेटा प्रबंधन की चुनौतियों तथा डेटा लोकलाइजेशन की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला।

डॉ शर्मिष्ठा दासगुप्ता ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की सभी पहलें "सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय" की मूल भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित प्रत्येक तकनीकी समाधान का उद्देश्य नागरिकों को सुलभ, पारदर्शी एवं प्रभावी डिजिटल सेवाएँ प्रदान करना है।

उन्होंने विशेष रूप से रेखांकित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग केवल तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका अंतिम लक्ष्य आम नागरिकों के जीवन को सरल बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को दक्ष बनाना तथा सुशासन को सुदृढ़ करना है।

मुख्य अतिथि डॉ. राजेश कुमार मिश्रा ने एन.आई.सी. में अपनी दीर्घ सेवा-यात्रा का उल्लेख करते हुए संगठन की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने उत्तर प्रदेश की डिजिटल इंडिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया तथा कहा कि उत्तर प्रदेश डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है।

इसके पश्चात श्री सुनील शर्मा, उपमहानिदेशक, ने न्यायालय संबंधी कार्यों में एन. आई. सी. की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नागरिक केंद्रित सेवाओं, ई-फाइलिंग, केस ट्रैकिंग प्रणाली तथा न्यायालय अधिकारियों के लिए विकसित डिजिटल मॉड्यूल्स के माध्यम से पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ाने के प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

उद्घाटन सत्र का समापन श्री अजय गोपाल भरतरिया, उपमहानिदेशक एवं अपर राज्य-सूचना विज्ञान अधिकारी (राज्य) द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर किया गया।`

तकनीकी सत्र : राज्य में एआई-संचालित डिजिटल आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में पहल

इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. शर्मिष्ठा दास गुप्ता द्वारा की गई। उन्होंने एन.आई.सी. द्वारा विकसित विभिन्न पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपने संबोधन में उन्होंने 'वाणी' (Voice Analytics आधारित उपकरण), 'तानी' (Text Analytics आधारित उपकरण), 'एआई-मात्रा' (Transliteration आधारित सेवा) तथा 'भाषिणी' (Translation आधारित उपकरण) जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी समाधानों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने यह भी बताया कि इस प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के दौरान किन-किन तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उन्होंने इन तकनीकी उपकरणों के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि ये डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में किस प्रकार महत्वपूर्ण परिवर्तन और सुधार ला सकते हैं।

इंडस्ट्री पार्टनर 'इंटेली डीबी' से श्री जयराज एवं श्री मनोराग सक्सेना जी ने अपने एआई आधारित टूल का प्रदर्शन किया, जो पोस्टग्रेएसक्यूएल (PostgreSQL) आधारित अनुप्रयोगों के अनुकूलन (ऑप्टिमाइज़ेशन) में सहायक है। इस टूल के माध्यम से डेटाबेस के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और एप्लिकेशन की कार्यक्षमता को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है।

इसके पश्चात श्री मयंक लाल शर्मा, जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी मैनपुरी जी द्वारा विकसित एआई आधारित अनुप्रयोग 'अघन्य' का भी प्रदर्शन किया गया। 'अघन्य' एक इमेज एनालिटिक्स आधारित टूल है, जो पशुओं के मज़ल (नाक/मुख) की तस्वीर को कैप्चर कर उनके सटीक पहचान में सहायता करता है। यह तकनीक पशुओं की पहचान के पारंपरिक तरीकों, जैसे ईयर टैगिंग, के कारण होने वाली पशु-क्रूरता को भी कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

तकनीकी सत्र : साइबर सुरक्षा के नवीनतम आयाम

दोपहर भोजन के पश्चात आयोजित सत्र की अध्यक्षता डॉ. आर. के. मिश्रा द्वारा की गई। उन्होंने एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा प्रतिभागियों को ऐसे नवाचारपूर्ण पहलों को आगे भी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत के डिजिटल परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनशील रुझानों पर संक्षेप में चर्चा करते हुए समय के साथ प्रासंगिक बने रहने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

इंडस्ट्री पार्टनरश्री शुभाशीष मुखोपाध्याय जी ने साइबर सुरक्षा विषय पर एक ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के महत्व और ऑनलाइन खतरों से बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला।

साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग के वैज्ञानिक 'बी' श्री हितेन सिंह द्वारा साइबर सुरक्षा विषय पर एक प्रस्तुति दी गई। अपने संबोधन में उन्होंने साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के प्रति जागरूक किया।

तकनीकी सत्र : डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

अंतिम सत्र में अन्य इंडस्ट्री पार्टनर 'वॉल्टाइज़' से श्री अनुराग द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम विषय पर प्रस्तुति दी गई। प्रस्तुति के दौरान उन्होंने बताया कि उद्योग जगत इस नए डेटा संरक्षण ढांचे के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रहा है तथा इसके अनुपालन के लिए विभिन्न तकनीकी और नीतिगत उपायों पर कार्य कर रहा है।

प्रथम दिवस का समापन श्री अजय गोपाल भरतरिया द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए दिनभर आयोजित सत्रों का संक्षिप्त उल्लेख किया, जिसके साथ ही कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ।

श्री आशेष कुमार अग्रवाल, राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी की अध्यक्षता में द्वितीय दिवस के सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव, सहायक अनुभाग अधिकारी तथा श्री नवनीत सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी ने विभिन्न सेवा नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं उपयोगी जानकारी प्रस्तुत की। प्रस्तुति में आईपीआर (IPR), एनपीएस (NPS) में पारिवारिक विवरण अद्यतन करना, एलटीसी (LTC) नियम, चिकित्सा सुविधाएँ (विशेष रूप से आपातकालीन मामलों में), इम्प्रेस्ट धनराशि, टूर अनुमोदन तथा सेवा पुस्तिका के सत्यापन से संबंधित प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया।

इस दौरान जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा कई प्रश्न पूछे गए, जिनका प्रशासन अनुभाग द्वारा विस्तार से उत्तर दिया गया। इससे प्रतिभागियों की विभिन्न शंकाओं का समाधान हुआ और उन्हें सेवा नियमों की बेहतर समझ प्राप्त हुई।

इसके पश्चात श्री शैलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) ने 'ई-ऑफिस' एवं 'ई-डिस्ट्रिक्ट' परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुति दी और इनके क्रियान्वयन में जिला सूचना-विज्ञान अधिकारियों (DIOs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी उस शासनादेश (GO) का भी उल्लेख किया, जिसमें राज्य अधिकारियों द्वारा वेतन प्राप्ति के लिए ई-ऑफिस के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

इसके पश्चात श्री प्रसून पांडेय, संयुक्त निदेशक (आईटी) द्वारा राज्य में 'ई-ऑफिस' के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के सभी जनपद 'ई-ऑफिस' पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं तथा 344 तहसीलें इस प्रणाली का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही हैं।

उन्होंने 'रेडी रेकनर' भी प्रस्तुत किया, जिसमें ई-ऑफिस से संबंधित सामान्य समस्याओं—जैसे ऑथराइजेशन त्रुटि, स्थानांतरण के बाद उपयोगकर्ता का दिखाई न देना, डीएससी (DSC) से संबंधित समस्याएँ—तथा उनके समाधान को संकलित किया गया है। इससे प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन हुआ।

श्री विनय कश्यप, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) द्वारा एन.आई.सी. जिला केंद्रों में नए आईसीटी हार्डवेयर की आपूर्ति के पश्चात आवश्यक स्टोर दस्तावेज़ीकरण तथा नीलामी के माध्यम से निष्प्रयोज्य घोषित वस्तुओं (obsolete items) के राइट-ऑफ से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।

श्रीमती शुभा श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित 'पोश अधिनियम (POSH Act)' के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। उन्होंने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व तथा कर्मचारियों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला।

श्री मयंक गोयल जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी बुलंदशहर द्वारा एन.आई.सी. उत्तर प्रदेश राज्य इकाई द्वारा विकसित 'ई-नगर सेवा' के क्रियान्वयन पर प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली को जनपद बुलंदशहर की सभी 17 नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे नागरिक सेवाओं के डिजिटलीकरण और सेवा वितरण में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिला है।

कार्यक्रम के अंत में खुली चर्चा एवं समापन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर अपर राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी (राज्य एवं जिला) द्वारा भी अपने-अपने प्रभार के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया। श्री पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) ने बताया कि प्रत्येक जिले में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से संबंधित प्रकरणों के लिए एक पृथक फाइल संधारित की जानी चाहिए, क्योंकि यह विषय संवेदनशील प्रकृति का है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि ई-मेल माइग्रेशन की प्रक्रिया के दौरान निष्क्रिय ई-मेल खातों को हटाया जाएगा, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से राजकोष पर व्यय का भार पड़ता है।

श्री अंशु रोहतगी, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) ने राज्य में बड़ी संख्या में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सफल संचालन के लिए जिला सूचना-विज्ञान अधिकारियों (DIOs) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एनएफई (NFEs) की उपस्थिति में समयपालन के महत्व पर भी बल दिया। वहीं श्री शैलेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक (आईटी) ने अवगत कराया कि राजभाषा दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु जिला स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड द्विभाषी (Bilingual) होना चाहिए।

अंत में श्री अजय गोपाल भरतरिया, उप महानिदेशक एवं अपर राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी (राज्य) ने 'दर्पण डैशबोर्ड' में प्रयुक्त रैंकिंग प्रणाली के बारे में जानकारी दी तथा निर्देशित किया कि जिला मजिस्ट्रेट की प्रोफाइल को नियमित रूप से अद्यतन किया जाए। उन्होंने जिला सूचना-विज्ञान अधिकारियों को अपने नवाचारों एवं पहलों को मीडिया समूह के साथ साझा करने के लिए भी प्रेरित किया, ताकि उन्हें डिजिटल माध्यमों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा सके।

कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों, मीडिया समूह तथा प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके सहयोग की सराहना की।

डी.आई.ओ. कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना, विभिन्न जिलों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

Two-Day Workshop for District Informatics Officers Organized by NIC Uttar Pradesh, Lucknow

As an important initiative towards strengthening digital governance, enhancing online security, and promoting innovative information technology solutions in the state, the National Informatics Centre (NIC), Uttar Pradesh State Centre organized a two-day State Level Workshop and Technical Interaction for officers working in District Informatics Centres (DIOs/ADIOs/DIAs) on 26–27 February 2026 at Yojana Bhawan, Lucknow. NIC Officers posted across Uttar Pradesh actively participated in the program.

The primary objective of the workshop was to review the progress and effectiveness of digital services being implemented at the district level, familiarize officers with emerging technological innovations, and develop a coordinated and forward-looking strategy in the fields of Cyber Security, Artificial Intelligence (AI), and e-Governance.

Inaugural and Address Session

The program commenced with a welcome address by Shri Ashesh Kumar Agrawal, State Informatics Officer (SIO). In his address, he emphasized the need to strengthen digital services at the district level, enhance coordination, and adopt innovation-driven working methodologies.

On this occasion, Shri Agrawal formally welcomed Chief Guest Dr. Rajesh Kumar Mishra, State Coordinator, NIC Uttar Pradesh, and Distinguished Speaker Dr. Sharmistha Das Gupta, Head of Group (AI Division) by presenting saplings as a token of respect.

In the first session of the program, Industry Partner Dr. Narendra Kumar Sharma delivered an insightful presentation on various aspects of Artificial Intelligence (AI). He elaborated on the role of high-quality data in AI systems, challenges in data management, and the importance of data localization.

Dr. Sharmistha Das Gupta, in her address, highlighted that all initiatives of the National Informatics Centre (NIC) are guided by the philosophy of "Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya". She emphasized that the primary objective of technological solutions developed by NIC is to provide accessible, transparent, and efficient digital services to citizens.

She further stressed that the use of Artificial Intelligence and advanced digital technologies is not limited to technological advancement alone but aims to simplify the lives of citizens, improve administrative efficiency, and strengthen good governance.

Chief Guest Dr. Rajesh Kumar Mishra shared insights from his long professional journey at NIC and highlighted the organization's growth over the years. He emphasized the crucial role of Uttar Pradesh in the Digital India mission, noting that the state is emerging as a leader in digital transformation.

Subsequently, Shri Sunil Sharma, Deputy Director General, NIC, spoke about NIC's role in judicial processes. He highlighted initiatives such as citizen-centric services, e-filing, case tracking systems, and digital modules for court officials, which contribute to transparency and efficiency in the judicial system.

The **inaugural session concluded with a vote of thanks presented by Shri Ajai Gopal Bhartaria, Deputy Director General and Additional State Informatics Officer(State).**

Technical Session: Building the AI-Powered Digital Backbone in the State

This technical session was chaired by Dr. Sharmistha Das Gupta. She provided detailed insights into various initiatives developed by NIC, including:

- VAANI – a Voice Analytics-based tool
- TAANI – a Text Analytics-based tool
- AI-MATRA – a Transliteration service
- BHASHINI – a Translation-based tool

She also highlighted the technological challenges involved in developing such advanced systems and emphasized the transformative potential of these tools in strengthening digital governance.

Industry partner IntelliDB, represented by Shri Jayaraj and Shri Manorag Saxena, showcased their AI-based tool designed to optimize PostgreSQL-based applications, which helps improve database performance and application efficiency.

Following this, Shri Mayank Lal Sharma, District Informatics Officer, Mainpuri, demonstrated an AI-based application "Aghanya."

"Aghanya" is an image analytics-based tool that captures the muzzle image of livestock to enable accurate identification. This innovative solution can help reduce animal cruelty caused by traditional identification methods such as ear tagging.

Technical Session: Emerging Dimensions in Cyber Security

The post-lunch session was chaired by **Dr. R. K. Mishra.** He appreciated the initiatives taken by NIC Uttar Pradesh and encouraged participants to continue pursuing such innovative efforts. He also briefly discussed the evolving digital landscape in India and emphasized the importance of remaining technologically relevant.

Industry partner **Shri Subhashish Mukhopadhyay** delivered an informative presentation on **cyber security,** highlighting the importance of digital safety and methods to mitigate online threats.

Additionally, **Shri Hiten Singh, Scientist-B from the Cyber and Information Security Division,** delivered a presentation on cyber security best practices. He explained important preventive measures to protect against cyber fraud and online scams, while encouraging participants to adopt safe digital practices.

Technical Session : Digital Personal Data Protection Act, 2023

In the final session of the day, industry partner Vaultize, represented by Shri Anurag, delivered a presentation on the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act. He explained how the industry is responding to the new data protection framework and highlighted various technological and policy measures being adopted to ensure compliance.

The **first day of the workshop concluded with a vote of thanks by Shri Ajai Gopal Bhartaria,** who expressed gratitude to all speakers and participants and briefly summarized the discussions held throughout the day.

Second Day Proceedings

The second day session was conducted under the chairmanship of **Shri Ashesh Kumar Agrawal, State Informatics Officer.**

On this occasion, **Smt. Richa Srivastava, Assistant Section Officer,** and **Shri Navneet Singh, Assistant Section Officer,** presented detailed information regarding various **service rules**, including:

- Immovable Property Returns (IPR)
- Updating family details in NPS
- Leave Travel Concession (LTC) rules
- Medical facilities, particularly emergency cases
- Imprest money procedures
- Tour approvals
- Service book verification

Participants raised several queries, which were addressed in detail by the Administration Section, helping to clarify doubts related to service matters.

Subsequently, **Shri Shailesh Srivastava, Senior Director (IT)** presented a brief overview of **e-Office and e-District initiatives,** highlighting the critical role of District Informatics Officers (DIOs) in its successful implementation. He also referred to the State Government order encouraging the use of **e-Office for salary processing by state officials.**

Following this, **Shri Prasoon Pandey, Joint Director (IT)** presented the **current status of e-Office rollout in the state,** informing that all districts have been onboarded and **344 tehsils are actively using the system.**

He also presented a **"Ready Reckoner"** addressing common issues such as authorization errors, user visibility problems after transfer, and **DSC-related issues,** along with their resolutions, which proved very useful for the participants.

Shri Vinay Kashyap, Senior Director (IT) provided information about **store documentation requirements following the delivery of new ICT hardware at NIC district centres,** as well as the procedure for **write-off of obsolete items through auction.**

Smt. Shubha Srivastava, Senior Director (IT) briefly introduced the **POSH Act (Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act)** and highlighted the importance of maintaining a safe and respectful workplace environment.

Shri Mayank Goyal, District Informatics Officer, Bulandshahr, presented the implementation of "**e-Nagar Sewa," developed by NIC Uttar Pradesh State Unit,** which has been successfully deployed across **all 17 Urban Local Bodies (ULBs) in Bulandshahr district**, significantly enhancing transparency and efficiency in citizen service delivery.

Open Discussion and Concluding Session

The workshop concluded with an **open discussion session,** where participants shared their experiences and suggestions.

During this session:

- **Shri Piyush Srivastava, Senior Director (IT)** advised that each district should maintain a dedicated file related to **Citizenship Amendment Act (CAA) cases** considering their sensitivity. He also informed that unused email accounts would be removed during the email migration process to reduce unnecessary expenditure.
- **Shri Anshu Rohtagi, Senior Director (IT)** appreciated the efforts of DIOs in managing the heavy volume of **Video Conferencing sessions** across the state and emphasized punctuality in attendance of NFEs.
- **Shri Shailesh Srivastava, Senior Director (IT)** informed that **Video Conferencing boards at district centres** should be bilingual in compliance with **Rajbhasha guidelines.**

Finally, **Shri Ajai Gopal Bhartaria, Deputy Director General and Additional State Informatics Officer,** explained the **ranking mechanism used in the DARPAN Dashboard** and instructed DIOs to ensure regular updating of **District Magistrate profiles.** He also encouraged officers to share their innovative initiatives with the media group for wider digital publication.

In his concluding remarks, he expressed gratitude to all organizing members, the media team, and participants for making the event successful.

The DIO Workshop aimed to strengthen IT-enabled governance in the state, enhance coordination among districts, and improve administrative efficiency through technology-driven initiatives. Officers from various districts of Uttar Pradesh actively participated in the program and contributed to meaningful discussions and knowledge sharing.